कमिश्नर सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नोएडा

बनाम

मेसर्स पंजाब फाइबर्स लिमिटेड, नोएडा

अपील (सिविल) 4647/2007

14 फरवरी 2008

[डॉ अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम, न्यायाधीश]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 - धारा 35 -एच(1) - संदर्भ आवेदन-भरने में देरी-विलंब-सीमा-धारित को माफ करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति

उच्च न्यायालय के पास संदर्भ आवेदन दाखिल करने में देरी के लिए खेद व्यक्त करने की शक्ति नहीं है क्योंकि धारा 35-एच में ऐसा कोई प्रावधान मौजूद नहीं है।

इन अपीलों में विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या उच्च न्यायालय के पास केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-एच के तहत संदर्भ की प्रस्तुति में देरी को माफ करने की शक्ति है।

अदालत ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया-

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-जी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील का प्रावधान करती है, जो विशेष रूप से कहती

है कि यह अपील उस तारीख से कुछ महीनों के भीतर होनी चाहिए, जिस दिन विवादित आदेश संप्रेषित किया जाता है। लेकिन धारा 35-जी का प्रावधान अपीलीय न्यायाधिकरण को धारा 1 में निर्धारित पूर्वोक्त सीमा समाप्त होने के बाद भी अपील की अनुमति देने की अनुमति देता है यदि न्यायाधिकरण संतुष्ट है कि निर्धारित समय के भीतर अपील दायर नहीं करने का पर्याप्त कारण था। धारा 35-ई(3) के अंतर्गत परिसीमा का प्रावधान किया गया है। क्षमादान की बाहरी सीमा बता दी गई है। धारा 35-एच में देरी माफ करने का ऐसा कोई प्रावधान मौजूद नहीं है। विधायी मंशा स्पष्ट है कि संसद ने कभी नहीं सोचा था कि धारा 35-एच के तहत संदर्भ आवेदन दाखिल करने में देरी को माफ किया जा सकता है। इस प्रकार, तत्काल मामले में, उच्च न्यायालय को यह मानना उचित था कि इसमें देरी को माफ करने की कोई शक्ति नहीं थी। संदर्भ आवेदन दाखिल करना। [पैरा 6,7 और 9] [863-ई-एफ,एच,एफ-जी;865-ई]

मेसर्स सिंह इंटरप्राइजेज बनाम सेंट्रल एक्साइज कमिश्नर, जमशेदपुर और अन्य 2007 (14) स्केल 610; पर भरोसा।

विनोद गुरुदास रायकर बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य 1991(4) एससीसी 333; संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4647/2007

सी.ई.आर.ए संख्या 06/2004 में उच्च न्यायालय इलाहाबाद के

निर्णय एवं आदेश दिनांक 07.02.2007 से

साथ

(सिविल अपील संख्या 4677,4678 और 5261/2007)

और

सिविल अपील संख्या 699-700/2006

साथ

(सिविल अपील संख्या 3560/2006, 4245, 4675 और 4676/2007)

अपीलकर्ता की ओर से बी कृष्ण प्रसाद

प्रतिवादी की ओर से सुमेश धवन

डॉ. अरिजीत पसायत, जे. -

1. इन सभी अपीलों में विचाराधीन प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय के पास केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 35-एच(1) के तहत संदर्भ की प्रस्तुति में देरी को माफ करने की शक्ति है।

2. निर्विवाद रूप से, इन सभी मामलों में संदर्भ आवेदन संदर्भ मांगने के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए प्रदान की गई अवधि से परे दायर किए गए थे। अधिनियम की धारा 35-एच इस प्रकार है:

"35-एच. केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त या अन्य पक्ष, उस तारीख से एक सौ अस्सी दिनों के भीतर, जिस दिन उसे धारा 35-सी के तहत एक आदेश का नोटिस दिया जा सकता है, जुलाई, 1999 के पहले दिन या उसके बाद पारित किया जा सकता है (जो कोई नहीं है) अन्य बातों के अलावा, उत्पाद शुल्क की दर या मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए माल के मूल्य से संबंधित किसी भी प्रश्न के निर्धारण से संबंधित आदेश, निर्धारित प्रपत्र में आवेदन द्वारा, जहां आवेदन किया जाता है अन्य पक्ष, दो सौ रुपये के शुल्क के साथ,अपीलीय न्यायाधिकरण को निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन करते हैं कि वह न्यायाधिकरण के किसी भी आदेश से उत्पन्न होने वाले कानून के किसी भी प्रश्न को उच्च न्यायालय में संदर्भित करें।

3. धारा 35-एच को वित्त अधिनियम, 1999 की धारा 128 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। उच्च न्यायालय ने संदर्भ आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसके पास संदर्भ के लिए आवेदन करने में देरी को माफ करने की कोई शक्ति नहीं है। यह नोट किया गया कि देरी को माफ करने की अनुमति देने

वाला कोई प्रावधान नहीं था।

4. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि भले ही अधिनियम में देरी के लिए किसी माफी का प्रावधान नहीं है। परिसीमा अधिनियम, 1963 के तहत एक प्रावधान है।

5. दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दृष्टिकोण का समर्थन किया।

6. इस समय, धारा 35-जी पर ध्यान देना उचित होगा जो अपील का प्रावधान करती है अपीलीय न्यायाधिकरण जो विशेष रूप से कहता है कि यह उस तारीख से तीन महीने के भीतर होना चाहिए जिस दिन आक्षेप लगाया गया है आदेश संसूचित किया जाता है। लेकिन धारा 35-जी का प्रावधान अपीलीय न्यायाधिकरण को इसके बाद भी अपील की अनुमति देने की अनुमति देता है यदि ट्रिब्यूनल संतुष्ट है कि ऐसा न करने का पर्याप्त कारण था तो खंड 1 में निर्धारित उपरोक्त सीमा समाप्त हो जाती है निर्धारित समय के भीतर अपील दाखिल करना। धारा 35-एच में देरी माफ करने का ऐसा कोई प्रावधान मौजूद नहीं है। दूसरे शब्दों में, विधायी मंशा स्पष्ट है कि संसद ने संदर्भ दाखिल करने में देरी का कभी इरादा नहीं किया था धारा 35-एच के तहत आवेदन माफ किया जा सकता है।

7. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 35-ई(3) के तहत परिसीमा का प्रावधान किया गया है। यहाँ फिर से, माफ़ी के लिए बाहरी सीमा का संकेत दिया गया है।

8. हाल ही में मेसर्स सिंह एंटरप्राइजेज बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, जमशेदपुर और अन्य, 1 (2007 (14)) में स्केल 610) निर्धारित अवधि से अधिक देरी को माफ करने की गुंजाइश पर विचार किया गया। इसे अन्य बातों के साथ-साथ नोट किया गया निम्नलिखितनुसार:

> "6. इस समय, अधिनियम की धारा 35 पर ध्यान देना प्रासंगिक है जो इस प्रकार है:
>
> "35. आयुक्त को अपील (अपील)।
>
> (1) केंद्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा इस अधिनियम के तहत पारित किसी भी निर्णय या आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त से निचले पद का अधिकारी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) आयुक्त [इसके बाद इस अध्याय में आयुक्त (अपील) के रूप में जाना जाता है] के समक्ष ऐसे निर्णय या आदेश की सूचना उसे भेजे जाने की तारीख से साठ दिनों के भीतर अपील कर सकता है:
>
> बशर्ते कि आयुक्त (अपील) यदि संतुष्ट है कि अपीलकर्ता

को साठ दिनों की उपरोक्त अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो वह इसे तीस दिनों की अतिरिक्त अवधि के भीतर प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है।

(2) इस धारा के तहत प्रत्येक अपील निर्धारित प्रपत्र में होगी और निर्धारित तरीके से सत्यापित की जाएगी।

7. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 11.5.2001 से 2001 के अधिनियम 14 द्वारा "साठ दिन" और "तीस दिन" की अवधि को "तीन महीने के भीतर" और "तीन महीने" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है।

8. केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील) और न्यायाधिकरण को क़ानून के तहत प्रदान की गई अनुमेय अवधि से परे देरी को माफ करने का अधिकार क्षेत्र निहित है। माफी की प्रार्थना किस अवधि तक स्वीकार की जा सकती है, यह वैधानिक रूप से प्रदान किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया कि देरी की माफी के लिए भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 (संक्षेप में 'सीमा अधिनियम') की धारा 5 के तर्क का लाभ उठाया जा सकता है। धारा 35 का पहला प्रावधान स्थिति को स्पष्ट करता है कि

निर्णय या आदेश की सूचना मिलने की तारीख से तीन महीने के भीतर अपील की जानी चाहिए। हालाँकि, यदि आयुक्त संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को 60 दिनों की उपरोक्त अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो वह इसे 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि के भीतर प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है। दूसरे शब्दों में, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अपील 60 दिनों के भीतर दायर की जानी है, लेकिन परंतुक के संदर्भ में अपील पर विचार करने के लिए अपीलीय प्राधिकारी द्वारा 30 दिनों का समय दिया जा सकता है। धारा 35 की उपधारा (1) का प्रावधान स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील को 30 दिनों की अवधि से अधिक प्रस्तुत करने की अनुमति देने की कोई शक्ति नहीं है। इस्तेमाल की गई भाषा स्थिति को स्पष्ट करती है कि विधायिका का इरादा अपीलीय प्राधिकारी को 60 दिनों की समाप्ति के बाद केवल 30 दिनों तक की देरी को माफ करके अपील पर विचार करने का था, जो अपील करने की सामान्य अवधि है। इसलिए, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का पूर्ण बहिष्कार है।

इसलिए आयुक्त और उच्च न्यायालय का यह मानना

उचित था कि 30 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद देरी को माफ करने की कोई शक्ति नहीं थी।"

9. उपरोक्त स्थिति के अनुसार, उच्च न्यायालय का यह मानना उचित था कि संदर्भ आवेदन दाखिल करने में देरी को माफ करने की कोई शक्ति नहीं थी।

10. विनोद गुरुदास रायकर बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य 2 (1991 (4) एससीसी 333) में इस न्यायालय ने देरी की माफी के संबंध में प्रश्न पर विचार किया।

"6. सामान्य धारा अधिनियम से स्वतंत्र होते हुए भी, यह दृढ़ता से स्थापित है कि जब तक कोई नया क़ानून स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से ऐसा नहीं कहता है, तब तक यह नहीं माना जाएगा कि यह किसी व्यक्ति को अर्जित अधिकार से वंचित करता है। दूसरी ओर, एक कानून जो प्रकृति में प्रक्रियात्मक है, और अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है, उसे पूर्वव्यापी रूप से लागू माना जाना चाहिए। प्रश्न यह है कि क्या अपीलकर्ता को वर्तमान मामले में अर्जित अधिकार या विशेषाधिकार से वंचित किया गया है।

7. यह सच है कि अपीलकर्ता पहले सीमा अवधि समाप्त

होने के छह महीने से अधिक समय बाद भी आवेदन दायर कर सकता था, लेकिन क्या इसे वह अधिकार माना जा सकता है जो अपीलकर्ता ने हासिल किया है। उत्तर नकारात्मक है. दुर्घटना के कारण मुआवजे का दावा, जिसका अपीलकर्ता हकदार था, निश्चित रूप से एक अधिकार के रूप में लागू करने योग्य था। जहां तक कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए सीमा अवधि का सवाल है, यह प्रकृति में विशेषण है, और इसे दो शर्तों के अधीन नए अधिनियम द्वारा शासित किया जाना है। यदि निरसन अधिनियम के तहत परिसीमा की छोटी अवधि के परिणामस्वरूप उपाय अचानक अवरुद्ध हो जाता है, तो इसे मामले को नियंत्रित करने के लिए नहीं माना जा सकता है, अन्यथा परिणाम वादी को अर्जित अधिकार से वंचित करना होगा। दूसरा अपवाद वह है जहां नया अधिनियम दावेदार को कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए इतनी कम अवधि के साथ छोड़ देता है ताकि उसके लिए उपाय का लाभ उठाना अव्यावहारिक हो जाए। इस सिद्धांत का इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में पालन किया गया है और उदाहरण के तौर पर हम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम श्रीमती शांति मिश्रा (1975 (2) एससीसी

840) का उल्लेख करना चाहेंगे। उस मामले में प्रतिवादी के पति की 1966 में एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। नुकसान की वसूली के लिए मुकदमा दायर करने के लिए प्रतिवादी को दो साल की अवधि उपलब्ध थी। मार्च, 1967 में मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 110 के तहत दावा न्यायाधिकरण का गठन किया गया, जिसमें सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार को छोड़कर 60 दिन की सीमा अवधि निर्धारित की गई। प्रतिवादी ने जुलाई, 1967 में आवेदन दायर किया। यह माना गया कि मार्च, 1967 से पहले मुकदमा दायर न करने पर प्रतिवादी का एकमात्र उपाय ट्रिब्यूनल के समक्ष आवेदन के माध्यम से था। जहां तक परिसीमा की अवधि का संबंध है, यह देखा गया कि छोटी अवधि प्रदान करने वाला परिसीमा का एक नया कानून निश्चित रूप से कार्रवाई के निहित अधिकार को समाप्त नहीं कर सकता है। कानून में बदलाव के मद्देनजर यह माना गया कि ट्रिब्यूनल के गठन के बाद उचित समय के भीतर आवेदन दायर किया जा सकता है; और, प्रतिवादी द्वारा इसके गठन के बाद ट्रिब्यूनल से संपर्क करने में लिए गए लगभग चार महीने के समय को या तो उचित समय माना जा सकता है या लगभग दो महीने की देरी को धारा 110-ए (3) के प्रावधानों

के तहत माफ किया जा सकता है।

8. विद्वान वकील ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि वर्तमान मामले को ऐसे मामले के रूप में माना जाना चाहिए जहां एक अर्जित अधिकार प्रभावित हुआ है, क्योंकि देरी से दायर देरी की माफी के लिए आवेदन दायर करने के विकल्प को एक अधिकार के रूप में माना जाना चाहिए। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता. मुआवज़े का दावा करने वाले आवेदन और ऐसे आवेदन दाखिल करने में हुई देरी को माफ करने की प्रार्थना के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। किसी अधिकार के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता अपने आप में कोई अर्जित अधिकार या विशेषाधिकार नहीं है। मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए, हम कुछ मामलों का उल्लेख कर सकते हैं।

XX XX XX

13. हमारे सामने मौजूद मामले में पुराने और नए अधिनियम के तहत दावा दायर करने की सीमा अवधि समान छह महीने थी जो नए अधिनियम के लागू होने के तीन सप्ताह बाद समाप्त हो गई। अपीलकर्ता के लिए यह खुला था कि वह इस अवधि के भीतर या बाद में 22

जुलाई, 1989 तक देरी को माफ करने की प्रार्थना के साथ अपना दावा दायर कर सकता था। मुआवज़े का दावा करने का उनका अधिकार एक अधिनियम के स्थान पर दूसरे अधिनियम से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। चूंकि परिसीमा की अवधि वही रही, इसलिए अपीलकर्ता को आश्चर्यचकित होने का कोई सवाल ही नहीं था। जहां तक छह महीने की देरी को माफ करने का सवाल था, नए अधिनियम के तहत स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। इस पृष्ठभूमि में अपीलकर्ता की आगे की चूक पर विचार किया जाना चाहिए। यदि किसी दिए गए मामले में दुर्घटना नए अधिनियम के लागू होने से एक वर्ष से अधिक समय पहले हुई थी और दावेदार ने वास्तव में अपनी याचिका तब दायर की थी जब पुराना अधिनियम लागू था लेकिन एक वर्ष की अवधि के बाद, स्थिति भिन्न हो सकती है। वास्तव में कार्यवाही शुरू करने के बाद जब पुराना अधिनियम इस क्षेत्र को कवर करता था तो एक दावेदार कह सकता था कि याचिका दायर करने पर प्राप्त उसका अधिकार छीना नहीं जा सकता। मौजूदा मामला अलग है देरी माफ़ी के प्रावधान के लाभ का दावा करने का अधिकार या विशेषाधिकार केवल देरी के समय लागू कानून द्वारा नियंत्रित किया जा सकता

है। यहां तक कि किसी अधिनियम का लाभ प्राप्त करने की आशा या अपेक्षा भी उस अधिनियम की प्रयोज्यता को पूर्व निर्धारित करती है जब उसका लाभ लेने की आवश्यकता उत्पन्न होती है। वर्तमान मामले में दावा दायर करने में देरी को माफ करने के प्रावधान का लाभ उठाने का अवसर पुराने कानून के निरस्त होने के बाद ही आया। जाहिर तौर पर 'पर्याप्त कारण' के रूप में स्थापित माफी का आधार निरसन के बाद के समय से भी संबंधित है। इसलिए, निरस्त कानून का लाभ केवल इसलिए उपलब्ध नहीं हो सका क्योंकि दावे के लिए कार्रवाई का कारण निरस्त होने से पहले उत्पन्न हुआ था। दावा दायर करने में देरी को माफ करने के आधार के रूप में 'पर्याप्त कारण' दावे के लिए 'कार्रवाई के कारण' से अलग है। इसलिए, देरी की माफ़ी का प्रश्न नए कानून द्वारा शासित होना चाहिए। हम तदनुसार मानते हैं कि उच्च न्यायालय का यह विचार सही था कि मामला नए अधिनियम के अंतर्गत आता है, और छह महीने से अधिक की देरी को माफ नहीं किया जा सकता है। अपील खारिज की जाती है, लेकिन इन परिस्थितियों में, बिना किसी लागत के।"

11. उपरोक्त स्थिति के अनुसार, लागत के संबंध में अपील बिना

किसी आदेश के खारिज कर दी जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अश्वनी कुमार विज, आर.जे.एस. अशोक कुमार मीना द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।